In regard to recruitment to Class III service which is done through the Railway Service Commissions, in addition to the directive mentioned above Chairman, Members of these Commissions are generally drawn from the Scheduled Caste/Tribe communities. Scheduled Castes/Tribes and minority communities contribute the majority of personnel on these Commissions.

Association of S.C./S.T. Representatives Association with working of Housing Committees on Railways

1195. SHRI S. M. SIDDAYYA:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether suitable instructions have been issued to the various Railway authorities to associate representatives of the Scheduled Castes/Tribes with the working of the Housing Committees set up under them; and

(b) if so, when were these instructions issued and whether these are being strictly followed by all concerned?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). Yes Instructions in this regard were issued by the Railway Board on 21st June, 1971 and are being followed wherever Housing Committees have been constituted. Railway Administrations which have not implemented these instructions so far, are being asked to do so.

Comprehensive information about posts reserved for S.C./S.T. in various Railways

1196. SHRI S. M. SIDDAYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether, as recommended in the Fifteenth Report of the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Fifth Lok Sabha) a brochure giving comprehensive information about the posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the various Railways, methods of recruitment, qualifications required and other concessions and facilities available for them has been published; and

(b) if so, whether a copy of that brochure will be laid on the Table of the House?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b). The Brochure on the lines of the one issued by the Department of Personnel is under compilation in this Ministry. Copies thereof will be supplied to the Parliament Library as soon as the same is printed and published.

अशोधित तेल का आयात करने के लिये करार

1197. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने गत दो वर्षों में कुल कितने तेल के आयात के लिये करार किये है ;

(ख) इन करारो के अधीन तेल उत्पादक देशों से कितना तेल आयात किया जायेगा ;

(ग) भारत को तेल सप्लाई करने वाले उन देशों के नाम क्या है जहां तेल पैदा नही होता ; और

(घ) उनके द्वारा सप्लाई किये जा रहे तेल का प्रति बैरल मूल्य क्या है और उनको भुगतान करने का तरीका क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मझी) (क) और (ख) . इण्डियन आयल कारपोरेशन ने ईराक, ईरान और सऊदी अरब की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ अशोधित तेल का आयात करने के लिए समझौता किया है जिसका विवरण नीचे दिया है :—

देश	आयात की जाने वाली मात्रा	जिस अवधि के दौरान आयात किया जायेगा व अवधि
ईरान .	3.95	1972–1975
ईराक	1.00	1974
सऊदी अरब	3.3	1973–1975

(ग) गैर-तेल उत्पादक देशों से अशोधित तेल का आयात नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न (ग) के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने की मांग

1198. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने के लिये मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मांग करने वाले व्यक्तियो दलों और संस्थाओं के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) इन मांगों को स्वीकार करने के लिये सरकार की क्या कठिनाइयां हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) . अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सदन के पटल पर रख दिये गये है । ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी–8505/74)

(ग) निस्संदेह उन सभी मांगों को जो वर्तमान निर्वाचन प्रणाली के सुधार से संबंधित सुझावों के रूप में रखी हुई है उस समय ध्यान में रखा जाएगा जब लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1973, जो कि इस समय लोक सभा में विचाराधीन है, विचारार्थ रखा जाएगा ।

Applications pending with Government for submission to MRTP Commission

1199. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a number of applications are pending with Government for submission to Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission for its clearance;

(b) if so, the particulars and salient features of such applications;

(c) whether the delay in processing of the applications by Government has resulted in failure in reaching the tragets of production by the applicants/industries; and

(d) if so, what steps have been taken to help to maintain the tempo of high production?